

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
कॉर्पोरेट कार्यालय, बीएचईएल, नई दिल्ली

संख्या: एए:एचआर:सीएसआर

दिनांक:

विषय: बीएचईएल की सीएसआर परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए
‘विशिष्ट एजेंसियों’ का पैनेल तैयार करना

आज, बीएचईएल ऊर्जा संबद्ध/मूलभूत क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरी और विनिर्माण उद्यम है। बीएचईएल की स्थापना 40 वर्षों से भी पहले हुई और यह 30 प्रमुख उत्पाद समूहों के अंतर्गत 180 से उत्पादों का निर्माण करता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे- विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, उद्योग, परिवहन, अक्षय ऊर्जा आदि को सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीएचईएल 15 विनिर्माण प्रभागों, पावर सेक्टर के चार क्षेत्रीय केन्द्रों, 100 से अधिक परियोजना स्थलों, 8 सेवा केन्द्रों, 18 क्षेत्रीय कार्यालयों और एक सहायक कम्पनी का व्यापक नेटवर्क है, जो कम्पनी को अपने ग्राहकों को तत्काल सेवा उपलब्ध कराने में समर्थ बनाता है और उन्हें दक्षतापूर्वक उपयुक्त उत्पाद, प्रणालियां और सेवाएं प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध कराता है।

बीएचईएल का विजन विश्व स्तर का इंजीनियरी उद्यम बनना है, जो स्टैकहोल्डर मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो। यह कम्पनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने तथा विश्व स्तर की कम्पनी बनकर देश की अपेक्षाओं पर खरी उतरने के लिए प्रयासरत है।

1. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में बीएचईएल गांवों को अंगीकृत करने, चिकित्सा शिविर लगाने, शिक्षण संस्थानों को समर्थन प्रदान करने, कौशल का विकास करने तथा बड़ी इकाइयों में विकलांग बच्चों हेतु स्कूल चलाने के लिए विभिन्न उपाय करता आया है। अब बीएचईएल ने लोक उद्यम विभाग के सीएसआर दिशानिर्देशों को अपना लिया है (प्रति संलग्न है)। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी गतिविधियों की सूची पृष्ठ 18 पर संलग्न है(अनुबंध-9)।
2. इनमें से चुनी गई तथा बीएचईएल के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई 8 प्राथमिक परियोजनाएं/गतिविधियां निम्नलिखित हैं:
 - a) पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा परिरक्षण

- b) आईटीआई की योग्यता प्राप्त लोगों का आत्मसात करण और कौशल विकास संस्थानों की स्थापना।
- c) व्यावसायिक प्रशिक्षण
- d) शिक्षा और प्रतिभा का उन्नयन
- e) गांवों को अंगीकृत करना तथा सामुदायिक विकास
- f) आपदा/विपदा प्रबंधन
- g) स्वास्थ्य प्रबंधन
- h) आधारभूत सुविधाओं का विकास

3. मैत्री संबंध स्थापित करके संधारणीय सामाजिक विकास में योगदान के लिए, बीएचईएल उन प्रतिष्ठित विशेष एजेंसियों, जैसे-एनजीओ/सामाजिक संगठनों आदि से प्रस्ताव/रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है, जो कम से कम 3 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और हमें सकारात्मक सहयोग दे सकती हैं। प्रस्ताव उपर्युक्त किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में, नई परियोजनाओं के लिए होने चाहिए, जिन्हें बीएचईएल के साथ शुरू किया जाएगा। इन परियोजनाओं के पर्याप्त लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। विस्तृत विवरण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों को भी देखा जा सकता है।

4. पंजीकृत निकायों/संगठनों के मामले में, रुचि की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:

- आवरण पत्र
- पंजीकरण प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन/न्यास विलेख
- पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षित लेखा/तुलनपत्र।
- आपके संगठन का प्रोफाइल, जिसमें पिछले/वर्तमान अनुभव का उल्लेख हो।
- संगठन के प्रमुख का प्रोफाइल
- प्रस्तावित भौगोलिक स्थिति, अर्थात् वह स्थान जहां परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
- प्रस्ताव से संभावित लाभ

5. एजेंसियों द्वारा आवेदन के लिए मुख्य विशिष्टियां इस प्रकार होंगी-परियोजना विशेष के लिए बेसलाइन स्टडी, अनुमानित बजट, लागत में बीएचईएल का हिस्सा और इसकी जिम्मेदारी का क्षेत्र, लागत में सहयोग करने वाली अन्य एजेंसियां, यदि कोई हों तो, लगने वाला समय, पूर्व-निर्धारित भौतिक और वित्तीय माइलस्टोन की समय सारणी, लाभग्राहियों की संख्या, लाभों का प्रकार, प्रत्याशित परिणाम आदि।

6. ये परियोजनाएं मुख्यतः बीएचईएल की इकाइयों अथवा भारत में किसी भी स्थान पर हो सकती हैं, जो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की उपर्युक्त विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होंगी। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी परियोजना/गतिविधियों का लाभग्राहियों/समाज पर संधारणीय विकास के लिए दीर्घावधि प्रभाव पड़ेगा।
7. इन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के मानदंड इस प्रकार होंगे- समुचित प्राधिकरण में पंजीकरण, आयकर छूट, विश्वसनीय और दोषरहित ट्रैक रिकॉर्ड, जिस समुदाय के लिए परियोजना शुरू की जानी है, उसमें आम स्वीकार्यता, क्या इन्हें पहले से सरकारी विभागों/निकायों आदि द्वारा पैनल पर लिया गया है/समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
8. इच्छुक एजेंसियों को संलग्न फॉर्मेट में ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे। बीएचईएल जिन एजेंसियों की परियोजनाओं/योजनाओं को समर्थन प्रदान करेगा, उनका चयन एक ऐसे पैनल से किया जाएगा, जो एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी और उनकी चालू परियोजनाओं में से चुनी हुई परियोजनाओं के सर्वेक्षण पर आधारित होगा और इसे अंतिम रूप से बोर्ड स्तर की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
9. बीएचईएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए उपलब्ध निधि से समर्थन के लिए परियोजनाओं के चयन हेतु अक्टूबर, 2010 के अंत तक प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मार्च, 2011 के अंत तक उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। इनमें से शेष आवेदनों तथा बाद में दिसम्बर, 2010 तक प्राप्त आवेदनों की जून, 2011 तक संवीक्षा की जाएगी और अंतिम रूप दिया जाएगा। तत्पश्चात, हर छः माह में एक बार यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जैसे-मार्च, 2011 वाले लॉट की संवीक्षा सितम्बर, 2011 तक और इसी प्रकार आगे भी।

किसी स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया महाप्रबंधक प्रभारी-एचएसई एवं सीएसआर से संपर्क करें।

महाप्रबंधक (प्रभारी)
एचएसई एंड सीएसआर
कॉर्पोरेट कार्यालय, बीएचईएल,
सीरी फोर्ट, नई दिल्ली - 110049
ईमेल: csr@bhel.in

भारत में बीएचईएल के सहयोग से समाज-सुधार परियोजनाओं के निष्पादन हेतु

रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदकों का विवरण

1/ संगठन का नाम :	
2/ निगमित होने की तारीख:	
3.0/ पंजीकरण संख्या:	
3.1/ राज्य सरकार के साथ:	कृपया ब्यौरा साथ लगाएं
3.2/ केन्द्र सरकार के साथ:	कृपया ब्यौरा साथ लगाएं
3.3/ आयकर छूट और संदर्भों के प्रमाणपत्र :	कृपया ब्यौरा साथ लगाएं
4/ प्रधान कार्यालय का पता:	
5/ बैंकों के नाम पते सहित:	
6/ राशि के स्रोत:	
7/ संगठन का ढांचा:	कृपया ब्यौरा साथ लगाएं
8/ भारत में स्थित कार्यालयों/शाखाओं के ब्यौरे:	कृपया ब्यौरा साथ लगाएं
9/ गत तीन वर्षों (2007-08, 2008-09, 2009-10) की अंकेक्षित रिपोर्ट और तुलन पत्र की प्रति	कृपया ब्यौरा साथ लगाएं
10.0/ कार्यक्षेत्र:	
10.1/ जुलाई'10 तक पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या:	कृपया "अनुबंध क" के अनुसार विवरण संलग्न करें
10.2/ जुलाई'10 को स्कीमों/परियोजनाओं की संख्या:	कृपया "अनुबंध ख" के अनुसार विवरण संलग्न करें
10.3/ जुलाई'10 को योजना/प्रोजेक्ट की शुरुआत	कृपया "अनुबंध ग" के अनुसार विवरण संलग्न करें

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कार्यालय की मुहर:

(नाम और पदनाम)

टिप्पणी: i/ कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें

ii/ सभी संलग्न कागजात मुहर लगे व हस्ताक्षर किए हों

सेवा में,

महाप्रबंधक (प्रभारी), एचएसई एवं सीएसआर,

कॉर्पोरेट कार्यालय, बीएचईएल हाउस,

सीरी फोर्ट, नई दिल्ली - 110049

अनुबंध "क"

पूरी की जा चुकी परियोजनाएं

जुलाई , 2010 को स्थिति

संगठन का नाम:	
पता:	

क्रम सं.	परियोजना का नाम और पता	क्षेत्र(शिक्षा,स्वास्थ्य, पर्यावरण)	परियोजना प्रबंधन (नाम और पता)	परियोजना की लागत (` / लाख)		निर्धारित समय				स्थिति (प्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव)
				अनुमानित	वास्तविक	शुरू होने का माह		समाप्त होने का माह		
						योजनाबद्ध	वास्तविक	योजनाबद्ध	वास्तविक	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

(नाम और पदनाम)

दिनांक:
टिप्पणी: कृपया बड़े अक्षरों में लिखें

कार्यालय की मुहर:

अनुबंध "ख"

वर्तमान (चालू)परियोजनाएं/योजनाएं

जुलाई , 2010 को स्थिति

संगठन का नाम:											
पता:											

क्रम सं.	परियोजना का नाम और पता	क्षेत्र(शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण)	परियोजना प्रबंधन (नाम और पता)	परियोजना की लागत (` / लाख)		निर्धारित समय				स्थिति (प्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव)
						शुरू होने का माह		समाप्त होने का माह		
				अनुमानित	संभावित	योजनाबद्ध	संभावित	योजनाबद्ध	संभावित	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

(नाम और पदनाम)

दिनांक:

टिप्पणी: कृपया बड़े अक्षरों में लिखें

कार्यालय की मुहर:

भविष्य की परियोजनाएं

जुलाई , 2010 को स्थिति

संगठन का नाम:							
पता:							

क्रम सं.	परियोजना का नाम और पता	क्षेत्र(शिक्षा,स्वास्थ्य, पर्यावरण)	परियोजना प्रबंधन (नाम और पता)	परियोजना की अनुमानित लागत (/ लाख)	निर्धारित समय		स्थिति (प्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव)
					शुरू होने का माह	समाप्त होने का माह	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

(नाम और पदनाम)

दिनांक:
टिप्पणी: कृपया बड़े अक्षरों में लिखें

कार्यालय की मुहर

15(3)/2007-DPE (GM)
Government of India
Department of Public Enterprises
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
New Delhi

GUIDELINES

ON

CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY

FOR

CENTRAL PUBLIC SECTOR

ENTERPRISES

MARCH 2010

INDEX

1. CONCEPT	3
2. PLANNING	4-5
3. IMPLEMENTATION	6-10
4. RESEARCH, DOCUMENTATION, ADVOCACY, PROMOTION AND DEVELOPMENT	11-12
5. FUNDING	13
6. CLARIFICATIONS	14
7. BASELINE SURVEY & DOCUMENTATION	15
8. MONITORING	16-17
9. ANNEXE	18-19

1. CONCEPT

1.1. Public Corporations have legal responsibilities to maximize shareholder profits; but a shift in corporate mindset led by social expectations and pressure is causing business leaders to rethink their responsibilities with respect to corporate performance measured in terms of economic impact, social impact and environmental impact - commonly called the **Triple Bottom Line**.

1.2. Economic growth is possible only through consumption of inputs available in the environment and society. The harnessing of natural resources has a direct impact on the economy, the environment and society at large. **Corporate Social Responsibility (CSR)** is a concept whereby organizations serve the interests of society by taking responsibility for the impact of their activities on customers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of their operations.

1.3. Corporate Social Responsibility is a Company's commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of its stakeholders. This commitment is beyond statutory requirements. Corporate Social Responsibility is, therefore, closely linked with the practice of **Sustainable Development**. Corporate Social Responsibility extends beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of social and business goals. These activities need to be seen as those which would, in the long term, help secure a sustainable competitive advantage.

2. PLANNING

2.1. The planning for Corporate Social Responsibility should start with the identification of the activities/projects to be undertaken. CSR projects/activities may be undertaken in the periphery where a company carries out its commercial activities as far as possible. Where this is not possible or applicable, a Company may choose to locate CSR projects anywhere in the country. Company specific Corporate Social Responsibility strategies should be developed that mandate the design of **Corporate Social Responsibility Action Plan** (Long-term, medium-term and short-term), with a shift from the casual approach to the **project based** accountability approach. The business plan under CSR should be integrated with the social and environment concerns related to the business of the company.

2.2. Selection of activities under CSR may be made to ensure that the benefits reach the smallest unit i.e. village, panchayat, block or district depending upon the operations and resource capability of the company. The approach to CSR planning needs to be shifted from an ad-hoc charity to a long-term sustainable approach. The Project Management and Monitoring skills available with the companies could be shared as far as possible, with the local administration by training and setting up required structures and systems.

2.3. The long-term Corporate Social Responsibility Plan should match with the long term Business Plan. This should be broken down into medium term and short term plans. Each of these plans should clearly specify:

- i) Requirements relating to baseline survey;
- ii) Activities to be undertaken;
- iii) Budgets allocated;
- iv) Time-lines prescribed;
- v) Responsibilities and authorities defined;
- vi) Major results expected.

2.4 Such plans should also clearly specify the implementation guidelines and the involvement of the implementing agency. The procedures and methodologies prescribed for monitoring should be highlighted as well as the modalities of the **concurrent** and **final evaluation**. Finally, there should be a clear specification regarding mandatory documentation of the experience.

3. IMPLEMENTATION

- a. CSR initiatives of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) should consider the following parameters for identification/selection of schemes/projects:
- (i) Thrust should be given wherever possible to areas related to the business of the CPSEs as a natural corollary to the business.
 - (ii) Investment in CSR should be project-based. Mere donations to philanthropic/ charity or other organizations would not come under the category of CSR.
 - (iii) CSR activities should generate community goodwill, create social impact and visibility.
 - (iv) For every project, the time-frame and periodic milestones should be finalized at the outset.
 - (v) CSR activities should also involve the suppliers in order to ensure that the supply-chain also follows the CSR principles.
 - (vi) CSR activities should help in building a positive image of the company in the public perception.
 - (vii) CSR activities may be related to United Nations Global Compact Programme on Environment.
 - (viii) CSR projects may be closely linked with the principles of Sustainable Development, based on the immediate and long-term social and environmental consequences of their activities.

- (ix) Every CPSE should shoulder responsibility for restoring / compensating for any ecological damage that is taking place as a result of its operations.
- (x) Care may be taken to ensure that CPSEs work towards fulfillment of the National Plan goals and objectives, as well as the Millennium Development Goals adopted by our country, ensure gender sensitivity, skill enhancement, entrepreneurship development and employment generation by co-creating value with local institutions/people.
- (xi) Central Public Sector Enterprises should redefine their business continuity plan to factor in hazards, risks and vulnerabilities. They should also create value in innovative social investments in the community and may focus on the areas of “Preparedness and Capacity Building” in Disaster Management (DM).
- (xii) Public-Private Partnership between the Government and the Central Public Sector could also be encouraged to leverage the strengths of the latter in Disaster Management. CPSEs need to network with the Ministries in Government of India / NDMA at the National level and State Governments / SDMA at the State level to strengthen and formalize their role in the DM process for ensuring preparedness of the communities towards disaster resilience.

3.2 Project activities identified under CSR are to be implemented by **Specialized Agencies** and generally NOT by staff of the CPSE concerned. Specialized Agencies could be made to work singly or in tandem with other agencies.

3.3 Such specialized agencies would include:-

- i) Community based organizations whether formal or informal;
- ii) Elected local bodies such as Panchayats;
- iii) Voluntary Agencies (NGOs);
- iv) Institutes/ Academic Organizations;
- v) Trusts, Missions, etc.;
- vi) Self-help Groups;
- vii) Government, Semi-Government and autonomous Organizations;
- viii) Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE);
- ix) Mahila Mandals/ Samitis and the like;
- x) Contracted agencies for civil works;
- xi) Professional Consultancy Organizations, etc.

3.4 CPSEs should generate awareness among all levels of their staff about CSR activities and the integration of social processes with business processes. Those involved with the undertaking of CSR activities should be provided with adequate training and re-orientation.

3.5 Initiatives of State Governments, District Administration, Local Administration as well as Central Government Departments/ Agencies, Self-Help Groups, etc., would be dovetailed/ synergized with the initiatives taken by the CPSEs.

3.6 Every care should be taken to ensure that there is no **duplication** of CSR activities undertaken by the CPSEs with that of programmes run by Central, State and Local Governments.

3.7 While assigning CSR projects to specialized agencies, every possible effort must be made to verify the reliability and clean track record of such agencies. CPSEs may make efforts to prepare suitable panels of such agencies or they may select from panels maintained by Government, Semi-Government, Autonomous Organization or the National CSR Hub, etc.

3.8 Activities related to Sustainable Development will form a significant element of the total initiatives of CSR.

3.9 Such activities should come under the 3 UN Global Compact Principles pertaining to the Environment. Businesses are asked to:

- i) Support a precautionary approach to environmental challenges;
 - ii) Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility;
- and

- iii) Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

3.10. Companies may also keep in mind the Environmental Management System as per ISO 14001.

4. RESEARCH, DOCUMENTATION, ADVOCACY, PROMOTION & DEVELOPMENT

4.1. The Department Of Public Enterprises, in conjunction with SCOPE and the CPSEs will create a **National CSR Hub** which will undertake/facilitate the following activities:

- i) Nation-wide compilation, documentation, and creation of database;
- ii) Advocacy;
- iii) Research;
- iv) Preparation of Panels of Implementing organisations/ monitoring and valuation Agencies;
- v) Promotional activities, including production of short films, printing of brochures, pamphlets etc.;
- vi) Conferences, Seminars, Workshops – both national and international;
- vii) Act as a Think Tank;
- viii) Any other matter as entrusted to it from time to time by the Department of Public Enterprises (DPE)

4.2 The National CSR Hub will begin operations with funding provided by Department of Public Enterprises. It will, however, be free to receive funds from:

- i) SCOPE and both Central as well as State PSEs;
- ii) UN Agencies, reputed international agencies such as World Bank, EU and other multilateral bodies and organisations;
- iii) Reputed National and State Bodies;
- iv) Government Departments, Autonomous Organisations, Planning Commission, Attached and Subordinate Offices, Corporations etc.
- v) Philanthropic Missions, Trusts, etc. of national and international repute.

4.3. Decisions relating to the location and functioning of the HUB will be taken by DPE. SCOPE will be kept informed of such decisions and will be free to offer suggestions, inputs etc.

5. FUNDING

5.1 The **CSR budget** will be mandatorily created through a Board Resolution as a **percentage of net profit** in the following manner:-

Type of CPSEs	Expenditure range for CSR in a Financial Year
Net Profit (Previous Year)	(% of profit)
(i) Less than Rs. 100 crore	3% – 5%
(ii) 100 crore to Rs. 500 crore	2% – 3% (Subject to a Minimum of 3 crores)
(iii) 500 crore and above	0.5% – 2%

5.2 Loss-making companies are not mandated to earmark specific funding for CSR activities.

5.3. They should achieve CSR objectives by integrating business processes with social processes wherever possible and taking up such initiatives which do not involve cash outgo, e.g., by synergising their CSR activities with those of other profit-making cos.

5.4. The CSR Budget should be fixed for each financial year. This funding will not lapse. It will be transferred to a **CSR Fund**, which will accumulate – as in the case of **non-lapsable pool** - for the North East.

5.5. In case CPSEs have different Profit Centers like Factories / Plant locations, they may be allocated separate CSR budgets to be spent by them under the Annual CSR Budget allocations.

6. CLARIFICATIONS

6.1. These Guidelines will supersede/override any other Guidelines/Circulars/Instructions etc. that may have been issued by any Ministry/ Department on any prior date. Guidelines on CSR for CPSEs will henceforth issue only from the Department of Public Enterprises.

6.2. These Guidelines are fully in consonance with the draft Guidelines for Corporates issued by the Ministry of Corporate Affairs as per their website.

6.3. Such companies who are operating in sectors such as financial services, and have no specific geographical area or limited area, would adopt and define the areas of their choice for undertaking CSR activities.

6.4. Activities and expenditure related to staff benefits will not count as CSR.

6.5. Also grants to organizations/ institutions that are not specifically implementing CSR projects specified by the CPSE would not count as CSR.

6.6. These Guidelines may be amended by the Department of Public Enterprises from time to time with the approval of the competent authority.

7. BASELINE SURVEY & DOCUMENTATION

7.1. The impact made by CSR activities should be quantified to the best possible extent with reference to base line data, which need to be created by the CPSEs before the start of any project. ***Hence Base-line Surveys are mandatory.***

7.2. Meticulous **documentation** relating to CSR approaches, policies, programmes, expenditures, procurement, etc., should be prepared and put in the ***public domain***, (particularly through the internet) and made available to the National CSR Hub.

8. MONITORING

8.1. Monitoring of the CSR projects is very crucial and needs to be a periodic activity of the Enterprise.

8.2. The Boards of CPSEs should discuss the implementation of CSR activities in their Board meetings.

8.3. Each CPSE should include a separate paragraph/chapter in the Annual Report on the implementation of CSR activities/projects including the facts relating to physical and financial progress.

8.4. The implementation of CSR guidelines will form a part of the Memorandum of Understanding that is signed each year between CPSEs and Government.

8.5. The performance of each CPSE with reference to its CSR activities should be monitored by the Ministry/Department concerned on a regular basis.

8.6. In MoU Guidelines from 2010-11 onwards, 5 marks have been earmarked out of the ***non-financial parameters*** for CSR activities and 5 marks for Sustainable Development initiatives.

8.7. For proper and periodic monitoring of CSR activities, companies may appoint a CSR committee or a Social Audit Committee or a suitable, credible **external** agency.

8.8 CSR projects should also be evaluated by an ***independent external agency***. This evaluation should be both **concurrent** and **final**.

9. ANNEXE

POSSIBLE AREAS OF ACTIVITIES UNDER CSR (THE LIST IS INDICATIVE AND NOT EXHAUSTIVE)

- i) Drinking Water Facility
- ii) Education
- iii) Electricity Facility
- iv) Solar Lighting System
- v) Health and Family Welfare
- vi) Irrigation Facilities
- vii) Sanitation and Public Health
- viii) Pollution Control
- ix) Animal Care
- x) Promotion of Sports and Games
- xi) Promotion of Art and Culture
- xii) Environment friendly technologies
- xiii) Promotion of livelihood for economically weaker sections through forward and backward linkages
- xiv) Relief to victims of Natural Calamities like earth-quake, cyclone, drought & flood situation in any part of the country
- xv) Supplementing Development Programmes of the Government.
- xvi) Non-conventional Energy Sources
- xvii) Construction of Community Centres/Night Shelters/Old Age Homes
- xviii) Imparting Vocational Training
- xviii) Setting up of skill development centres.

- xix) Adoption of villages
- xx) Taking action on points suggested by Ministry of Forest and Environment pertaining to Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection for 17 categories of Industries.
- xxi) Scholarships to meritorious students belonging to SC, ST, OBC and disabled categories.
- xxii) Adoption/Construction of Hostels (especially those for SC/ST and girls),
- xxiii) Skill training, entrepreneurship development and placement assistance programmes for youth.
- xxiv) Building of Roads, Pathways and Bridges.
- xxv) Entrepreneurship Development Programme (EDP)
- xxvi) Disaster Management Activities including those related to amelioration/ mitigation.
- xxvii) Activities related to the preservation of the Environment/Ecology and to Sustainable Development